भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3463

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

3463. श्री खगेन मुर्मु:

श्री अनन्त नायक:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में निर्माण, मोटर वाहन और रक्षा उद्योग के लिए इस्पात की आवश्यकता बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक नई उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य में एक नई इस्पात उत्पादन इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त वर्ष 2025 में इस्पात क्षेत्र का कार्य-निष्पादन कैसा रहा और पिछले वर्षों की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ड.) निर्माण, मोटर वाहन और रक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों में इस्पात क्षेत्र का प्रभाव, उत्पादन, खपत और इस्पात की घरेलू मांग में वृद्धि के आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ड.) निर्माण और अवसंरचना, मोटर वाहन और रक्षा क्षेत्र भारत की इस्पात खपत का लगभग 90% योगदान करते हैं। इन क्षेत्रों में इस्पात के प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:-

निर्माण क्षेत्र: इस्पात सरकार के बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विस्तार जैसे राजमार्ग, पुल, रेलवे, मेट्रो प्रणाली और किफायती आवास कार्यक्रमों के निर्माण का अभिन्न अंग है।

मोटर वाहन क्षेत्र: इस्पात का उपयोग चेसिस, बॉडी पैनल और इंजन पार्टस सहित कई प्रकार के घटकों के निर्माण में किया जाता है। मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने घरेलू स्तर पर उत्पादित इस्पात की मांग में वृद्धि की है।

रक्षा क्षेत्र: देश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा निवेश में वृद्धि के साथ-साथ विशेष, उच्च शक्ति वाले इस्पात मिश्र धातुओं की आवश्यकता बढ़ी है। भारत की विस्तारित रक्षा अवसंरचना, जैसे अड्डे और भंडारण सुविधाओं में भी इस्पात महत्वपूर्ण है।

जारी...2/-

(ख): देश के भीतर विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए जुलाई, 2021 में सरकार द्वारा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई थी। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 24 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता का सृजन होगा और 14,760 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार ओडिशा सहित देश के सभी राज्यों में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में उद्योग द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, बंदरगाह से दूरी, लॉजिस्टिक आदि शामिल हैं। निम्न तालिका पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात उत्पादन और खपत में वृद्धि को दर्शाती है:

वर्ष	**कच्चा इस्पात (एमएनटी में)**	**तैयार इस्पात (एमएनटी में)**	
	उत्पादन	**उत्पादन**	**खपत**
2019-20	109.14	102.62	100.17
2020-21	103.54	96.20	94.89
2021-22	120.29	113.60	105.75
2022-23	127.20	123.20	119.89
2023-24	144.30	139.15	136.29
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, एमएनटी-मिलियन टन			

******